3 खिलाडियों ने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया

5 भारतीय राजनीति में प्रतिष्ठित नाम

6 वन दिवसः वैश्विक होती दुनिया में पेड़

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 46 प्रति सोमवार, 24 मार्च 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

पुलिसकर्मियों के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं पर कमलनाथ ने किया वार

- **मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ ने पुलिसकर्मियों को दी थी साप्ताहिक अवकाश की सौगात**
- **मऊगंज में हुई एएसआई की मौत की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कानून व्यवस्था पर विधानसभा में खड़ा किया सवाल**

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश में जिन कंधों पर प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ जनता की सुरक्षा की जवाबदेही है। आज वही कंधे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्यप्रदेश पुलिस के उन सिपाहियों की जिनके साथ पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग घटनाएं हुई। इसमें किसी के साथ अभद्रता की गई तो किसी की हत्या ही कर दी गई। जनता की सुरक्षा का सूत्र लेकर प्रदेश में तैनात पुलिस के वर्दीधारी सिपाहियों की जिंदगी की चिंता आखिर कौन करेगा। मध्यप्रदेश शांति का टापू है। ऐसे में प्रदेश में हर तरह की आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिसकर्मी मुस्तैदी के साथ तैनात रहते हैं। लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि वर्दीधारी खुद ही सकते में हैं। वे हर कदम बढ़ाने से पहले एक बार अपना और अपने परिवार के लोगों की सुरक्षा और उनकी चिंता करने को मजबूर हो गये हैं।

कमलनाथ ने उठाया विधानसभा में मुद्दा

पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं। उन्होंने पिछले दिनों मप्र के सिपाहियों के साथ हुई घटनाओं की न्यायिक जांच की मांग करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कमलनाथ ने विधानसभा में पुलिस सुरक्षा कानून एक्ट लागू करने और उसके तहत अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हुए प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवालियां निशान खड़े कर दिये। कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश कानून अव्यवस्था की राजधानी बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की राजधानी बनता जा रहा है। पूरा देश आज मध्य प्रदेश की तरफ देख रहा है और ये हालात हैं। (शेष पेज 2 पर)

पूर्व मुख्य सचिव भू-माफिया विवेक ढांड पर क्यों मेहरबान हैं छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी और ईओडब्ल्यू?

- **20 हज़ार रुपये प्रतिवर्ग फुट में नजूल की जमीन विवेक ढांड ने बेच दी डी-मार्ट को**

-विजया पाठक

पूर्व मुख्य सचिव भू-माफिया विवेक ढांड पर छत्तीसगढ़ सरकार की छत्रछाया क्यों बरकरार हैं? यह गंभीर सवाल है, इसके भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं की जा रही? जबकि बहुचर्चित महादेव सट्टा एप मामले में, बहुचर्चित शराब घोटाले में भी भू-माफिया विवेक ढांढ का नाम सामने आया था। साथ ही छत्तीसगढ़ में एक हजार करोड़ के एनजीओ घोटाले में भी विवेक ढांड का नाम है। भी विवेक ढांड का नाम सामने आया। इसके साथ ही पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के फ्री होल्ड के आदेश को निरस्त करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने विवेक ढांड को खुली छूट क्यों दे दी? परिणामस्वरुप नजूल की जमीन को बेचने का कार्य विवेक ढांढ ने कर दिया। सूत्रों प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 हजार रुपये प्रति वर्गफीट में जमीन बेची गई है। जिसकी कीमत लगभग 300 करोड़ रुपये से ऊपर आंकी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो इसकी प्रकरण की जांच क्यों नहीं कर रहा है।

रायपुर की लगभग सभी हाऊसिंग बोर्ड की कालोनियों के आसपास की जमीन विवेक ढांड एंड कंपनी जिसमें एक सीए जैन और उसके आदमियों का नाम दर्ज है। ये सब हुआ था जब वर्तमान रेरा अध्यक्ष आईएफएस संजय शुक्ला हाऊसिंग बोर्ड के पदाधिकारी थे। संजय शुक्ला विवेक ढांड के रेरा में उत्तराधिकारी बनकर बैठे हैं। इनकी भी अरबों की नामी बेनामी संपत्तियां हैं, जिनकी शिकायत छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के पास लंबित है। इन पर भी ईओडब्ल्यू क्यों मेहरबान है? (शेष पेज 2 पर)

पूर्व मुख्य सचिव भू-माफिया विवेक ढांड पर क्यों मेहरबान हैं छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी और ईओडब्ल्यू?

(पेज 1 से जारी)

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव भू-माफिया विवेक ढांड के काले कारनामें

नजूल की 1,53,000 वर्गफिट जमीन पर कब्जा करके पहले 1964 के फ़र्ज़ी रजिस्ट्री दस्तावेज तैयार कर उन्हें आईएएस अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा से सत्यापित करवाया। जमीन के बाद में आवासीय उपयोग के लिये नजूल के पट्टे बनवाये गए। नजूल भूमि ब्लॉक नम्बर 15 प्लॉट नम्बर 17/38 क्षेत्रफल 23000 वर्गफीट। प्लॉट नम्बर 17/39 क्षेत्रफल 37000 वर्गफीट विवेक कुमार ढांड आत्मज स्व. श्री सतपाल ढांड, डॉ. श्रीमती रंजना खोसला आत्मज स्व. श्री सतपाल ढांड, कुमारी साधना ढांड आत्मज स्व. श्री सतपाल ढांड, डॉ. श्रीमती अरुणा पलटा के नाम पर नजूल का पट्टा लिया। आम जनता को जहाँ आवास के लिए जमीन नहीं मिल पाती, जहाँ हजारों-लाखों की संख्या में लोग किराए के मकान में अपना सारा जीवन गुजार देते हैं, वहीं भू-माफिया, रसूखदारों के लिए शासकीय आबादी जमीन वरदान साबित होती है।

जानें कौन हैं पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड?

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड को इस पूरे घोटाले का मास्टर माइंड बताया गया है। ईडी ने इस मामले में पूर्वमंत्री कवासी लखमा को भी गिरफ्तार किया है। कवासी लखमा छत्तीसगढ़ सरकार में आबकारी विभाग के मंत्री थे। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में पेश किए गए आवेदन में विवेक ढांड को पूरे घोटाले का मास्टर माइंड बचाया गया है। कहा गया है कि ढांड के निर्देशन में अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और अरुणपति त्रिपाठी काम कर रहे थे। यह भी दावा किया गया है कि घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी विवेक ढांड को हिस्सेदारी भी दी गई है। विवेक ढांड 1981 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। ढांड 1 मार्च 2014 को राज्य के मुख्य सचिव बने थे। उनके नाम सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव बने रहने का रेकॉर्ड है। वह 03 साल 07 महीने से ज्यादा समय तक राज्य के मुख्य सचिव रहे। विवेक ढांड भूपेश बघेल की सरकार में नवाचार आयोग के अध्यक्ष पद पर काम कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

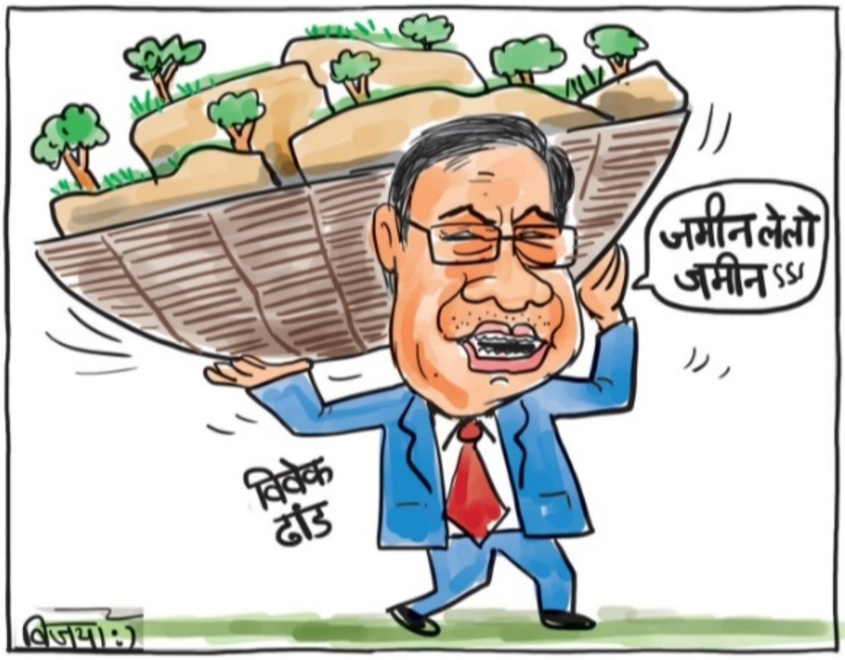

कंपनियों से कराते थे शराब का अवैध उत्पादन

दावा किया गया है कि शराब घोटाले में शामिल लोग शराब कंपनियों से शराब का अवैध उत्पादन करवाते थे। इस अवैध शराब की सप्लाई शराब घोटाले के सिंडिकेट चलाते थे। जिसके बदले में उन्हें कमीशन मिलता था। ईडी के अनुसार, 2019 से 2022 तक लाइसेंसी शराब की दुकानों पर नकली होलोग्राम लगाकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब बेची जाती थी। जिससे राजस्व विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस घोटाले का खुलासा कांग्रेस की सरकार में हुआ था। ईडी ने इस मामले में कई सीनियर अधिकारियों और कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। शराब घोटाले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा समेत कई अधिकारी और कारोबारी जेल में हैं।

कवासी लखमा के घर में हुई थी रेड

शराब घोटाले को लेकर ईडी की टीम ने 28 दिसंबर को पूर्व मंत्री कवासी लखमा के यहां रेड की थी। ईडी ने दावा किया था कि कवासी लखमा के घर से उसे घोटाले में शामिल होने के कई सबूत मिले हैं। ईडी की पूछताछ में आबकारी विभाग के अधिकारी इकबाल खान और जयंत देवांगन ने इस बात की पुष्टि की थी कि वह लोग पैसों की व्यवस्था करके पूर्व मंत्री को भेजते थे। वहीं, भेजी गई सरकार को सुकमा में कन्हैयालाल कुर्रे कलेक्ट करता था।

पुलिसकर्मियों के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं पर कमलनाथ ने किया वार

(पेज 1 से जारी)

पुलिस के लिये साप्ताहिक अवकाश की थी पहल

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पुलिसकर्मियों के जीवन और उनके स्वास्थ्य लेकर सुरक्षा तक को लेकर कितने चिंतित हैं इस बात का अंदाजा इससे ही लगता है कि उन्होंने अपने 18 महीने के कार्यकाल में पुलिसकर्मियों के हित में कई प्रमुख फैसले लिये। कमलनाथ प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने पुलिस जवानों के साप्ताहिक अवकाश की पहल की और उच्चाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए राज्य की कानून व्यवस्था को दुरस्त करने में जुटे इन वर्दीधारियों के मान-सम्मान की भी बात की।

एक नहीं कई प्रमुख फैसले किये

कमलनाथ ने पुलिसकर्मियों के पक्ष में एक नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण फैसले लेकर पुलिस व उनके परिवार को आर्थिक व सामाजिक संबल दिया। कमलनाथ ने पुलिस बल के लिये आपात परिस्थितियों में अवकाश उपयोग नहीं करने पर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था हो। पुलिस व्यवस्था में तकनीकी संसाधनों को आधुनिक किया जाये। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आपराधिक और गैर कानूनी गतिविधियों के प्रति जीरो टालरेंस रखें। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये समग्र दृष्टिकोण के साथ रणनीति बनायी जाये। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के नियंत्रण के लिये संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ कार्य किया जाये। कमलनाथ का मानना है कि सुशासन (गुड-गवर्नेंस) का प्रमुख आधार पुलिस बल है। राज्य की छवि पुलिस व्यवस्था पर निर्भर है।

इसलिए उठी पुलिस सुरक्षा की मांग

दरअसल मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में बीते दिनों भड़के दंगे में एक एएसआई की मौत हो गई थी। जबकि थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी और तहसीलदार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मऊगंज जिले के शाहपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब आदिवासी युवक की मौत को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। इस हमले में ASI रामचरण गौतम की मौत हो गई थी। हालात इतने बिगड़ गए कि आरोपियों ने पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया, जिसके बाद भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा।

कानून व्यवस्था पर उठाये सवाल

मध्यप्रदेश में पुलिसकर्मियों के साथ हुई इन सभी घटनाओं के बाद कमलनाथ ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाएं हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में पुलिस कहीं पीट रही है तो कहीं पिट रही है। ये देश का पहला ऐसा प्रदेश है। कमलनाथ ने कहा कि आज प्रदेश की स्थिति ये है कि कहीं पुलिस पीट रही है तो कही पिट रही है। ये देश का एक ऐसा प्रदेश है, जहां पुलिस पीटती भी है पिटती भी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में पुलिस भी असुरक्षित है। ऐसी स्थिति में जनता कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाब मांग रही है।

गाडरवारा में जंक्शन बनने का सपना टूटा

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। गाडरवारा में 2016-17 में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की पहल पर जबलपुर-गाडरवारा-बुधनी-इंदौर रेल मार्ग लगभग 4200 करोड़ रुपए की लागत से बनने के लिए रेल बजट में स्वीकृत हुआ था। जिससे गाडरवारा में जंक्शन बनने की उम्मीद जागी थी। इससे गाडरवारा क्षेत्र के साइखेड़ा से लोगों के साथ उदयपुरा-रायसेन के लोगों को भी सीधे रेललाइन की सुविधा होने की आस जगी थी। परंतु पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद दोनों को गाडरवारा से जंक्शन बनने की गहरी आपत्ति थी। जिसके लिए उन्होंने संसद में भी इसके लिए आवाज उठाई थी। यही कारण है कि, आपसी सहमति नहीं होने के कारण विगत 8-9 वर्षों में बजट में गाडरवारा बुधनी मार्ग के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई। जबकि बुधनी इंदौर रेल मार्ग के लिए लगातार राशि स्वीकृत हुई तथा वहां कार्य को गति देने के लिए लगातार सतत प्रक्रिया चल रही है। और अब रेल मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि अब गाडरवारा से बुधनी मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इसके लिए लगातार विगत 5-6 वर्षों से जनता में आस थी कि वर्षों पूर्व का यह वादा अब साकार रूप ले सकता है किंतु वर्तमान के जनप्रतिनिधियों की तानातनी एवं आपसी महत्वाकांक्षाओं के कारण यह सपना अब अधूरा ही रह जायेगा। नरसिंहपुर जिले में दो-दो मंत्रियों के पास 04 मंत्रालय होने बाद इतनी बड़ी परियोजना का रद्द हो जाना यह दर्शाता है कि राज्य सरकार से केंद्र तक उनका कद कितना बचा है वहीं रायसेन जिले में भी मप्र शासन में आवश्यक जिम्मेदारी सम्हाल रहे मंत्री भी आने जिले में स्टेशन तो छोड़िए पटरियों की सौगात तक नही दे पाए हैं। तीन मंत्रियों एवं पार्टी में प्रदेश के किसानों के प्रमुख स्थानीय सांसद का यह बेरुखापन जनता के लिए बडा ही गैर जिम्मेदाराना है जहां पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केंद्रीय कृषिमंत्री अपने क्षेत्र बुधनी से मंगलियागांव तक तक नया ट्रैक जोड़कर एवं बुधनी में मुख्यमंत्री को बुलाकर मंचों से नवीन विकास की सौगात पर सौगात परोस रहे।

खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय पटल पर रोशन किया: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित राष्ट्रीय खेल विजेता सम्मान समारोह में गोवा और उत्तराखंड नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेता खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ का गौरव बताते हुए कहा कि आप सभी ने अपनी मेहनत, प्रतिभा और जुनून से छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय पटल पर रोशन किया है। ये सिर्फ आपकी नहीं, पूरे प्रदेश की जीत है। आप प्रदेश के खेल जगत के हीरे हैं। सरकार आपको तराशेगी, निखारेगी और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाएगी। आपके लिए हर संभव संसाधन और समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने समारोह में गोवा में वर्ष 2023 में सम्पन्न 37वें नेशनल गेम में छत्तीसगढ़ के पदक विजेता 72 खिलाड़ियों को और वर्ष 2025 में उत्तराखंड में सम्पन्न 38 वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ पदक विजेता 58 खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हम लोगों ने गोवा में पदक जीतने वाले राज्य के 72 खिलाड़ियों को 01 करोड़ 07 लाख 60 हजार रुपए की राशि एवं उत्तराखंड में नेशनल गेम्स जीतने वाले 58 खिलाड़ियों को 87 लाख 60 हजार रुपए की राशि प्रदान कर सम्मानित किया है। इस प्रकार समारोह के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 130 राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को कुल 01 करोड़ 95 लाख 20 हजार रुपए की सम्मान राशि हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के खाते में अंतरित की जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश के जो भी खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में पदक लाएंगे, उनके लिए विशेष पुरस्कारों की घोषणा हमारी सरकार ने की है। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को तीन करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दो करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को एक करोड़ रुपए देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। इस अवसर पर खेल विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, संचालक श्रीमती तनुजा सलाम, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव विक्रम सिसोदिया उपस्थित थे।

एम्स भोपाल में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस पर जागरूकता सत्र का आयोजन

-समता पाठक

जगत प्रवाह. भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में संस्थान ने विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के अवसर पर पीडिएट्रिक ओपीडी में जागरूकता सत्र का आयोजन किया। डॉ. भावना ढींगरा के नेतृत्व में आयोजित इस सत्र का उद्देश्य डाउन सिंड्रोम, इसकी चुनौतियों और प्रारंभिक हस्तक्षेप तथा समावेशी देखभाल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इस कार्यक्रम में माता-पिता, देखभाल करने वाले और स्वास्थ्यकर्मियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। संवादात्मक गतिविधियों और सूचनात्मक चर्चाओं के माध्यम से, सत्र में डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों के लिए सामुदायिक समर्थन और समावेशी शिक्षा के अवसरों की आवश्यकता पर बल दिया गया। प्रोफेसर (डॉ.) अजय सिंह ने एक अधिक समावेशी समाज बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "एम्स भोपाल में हम डाउन सिंड्रोम जैसी आनुवंशिक स्थितियों के बारे में व्यापक देखभाल प्रदान करने और जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे जागरूकता सत्र समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक सहायक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।" कार्यक्रम के अंत में, एक "ओपन फोरम" का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उपस्थित दर्शकों को प्रश्न पूछने और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करने का अवसर प्रदान करना था। एम्स भोपाल ने परामर्श, चिकित्सीय सहायता और जागरूकता पहल के माध्यम से बच्चों और उनके परिवारों के प्रति अपनी सतत प्रतिबद्धता दोहराई।

वन केवल ऑक्सीजन ही नहीं, बल्कि पोषण, रोजगार और संस्कृति का भी स्रोत हैं: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-आनंद शर्मा

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वर्ष 2025 का विश्व वानिकी दिवस 'फारेस्ट एंड फूड' थीम पर आधारित है, जो इस बात पर बल देता है कि वन केवल ऑक्सीजन ही नहीं, बल्कि पोषण, रोजगार और संस्कृति का भी स्रोत हैं। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने 'वाइल्ड एडिबल प्लांट्स इन छत्तीसगढ़ स्टेट' पुस्तक का विमोचन किया तथा पुदीना-मिंट फ्लेवर के बस्तर काजू प्रोडक्ट को लॉन्च भी किया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के समिति कक्ष में आयोजित विश्व वानिकी दिवस संगोष्ठी में शामिल होकर प्रदेशवासियों को वन संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का 'ऑक्सिजोन' बनकर पूरे भारत को ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश का 44 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है, जो न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत का अभिन्न हिस्सा भी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 32 प्रतिशत आबादी जनजातीय भाई बहनों की है जो वनों के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार वनों में निवासरत जनजातीय भाई-बहनों को वनाधिकार पट्टे प्रदान कर रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और खेती की दिशा में आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ की नैसर्गिक सुंदरता की सराहना करते हुए कहा कि यहां के जलप्रपात, वनवासी संस्कृति और समृद्ध जैव विविधता पूरे देश के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। बस्तर का धूड़मारास अब विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थान बना चुका है। पर्यटन का विस्तार हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में लगभग चार करोड़ वृक्ष लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर में पीपल फॉर पीपल कार्यक्रम के अंतर्गत हर चौराहे पर पीपल का रोपण किया गया है, जो भविष्य में शुद्ध ऑक्सीजन का सशक्त स्रोत बनेंगे। पीपल का पेड़ वैज्ञानिक रूप से सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है, और यह पहल शहरी हरियाली की दिशा में एक प्रभावी कदम है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के वन विश्व के सबसे सुंदर वनों में गिने जाते हैं। साल और सागौन के वृक्ष यहां की प्राकृतिक शोभा हैं। साल के वनों में एक अनूठा सम्मोहन है और यह गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक जंगल हैं, तब तक जीवन है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदायों का पूरा जीवन वनों पर आधारित है। उनका जीवनस्तर ऊँचा उठाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से जूझ रही है और इसका सबसे कारगर उपाय वन क्षेत्र का विस्तार है। उन्होंने कहा कि हमारे आदिवासी भाई-बहनों के पास प्रकृति का अनुभवजन्य ज्ञान है– उसका समुचित उपयोग कर हम विकास और संरक्षण दोनों को संतुलित कर सकते हैं। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, योगेश्वर राजू सिन्हा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव तथा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सम्पादकीय

चार दशक बाद फिर दिल्ली नरसंहार की घटना पर शुरू हुई चर्चा

15,826 दिन से दिहुली नरसंहार के पीड़ित न्याय का इंतजार कर रहे थे। 18 नवंबर 1981 को डाकुओं ने 24 लोगों की हत्या कर गांव में खून से होली खेली थी। मारे गए लोगों की चीखें जब दिल्ली तक पहुंची तो एक हफ्ते के अंदर अपने सारे काम काज छोड़ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गांव पहुंची थीं। यहां उन्होंने मारे गए दलितों के परिवार वालों से वादा किया था कि, दोषियों को सजा अवश्य मिलेगी। 43 साल 4 महीने बाद जब आरोपी बनाए 17 में 13 लोगों की मौत हो गई तो अदालत ने फैसला सुनाया है। इस मामले में आज तक एक आरोपी ज्ञानचंद फरार है। जब अदालत ने नरसंहार में शामिल तीन डाकुओं को फांसी की सजा सुनाई तो वे रोने लगे वहीं दिहुली गांव में दलित परिवारों ने होली खेली गई। कहते हैं देर से मिला न्याय अन्याय से कम नहीं... फिरोजाबाद के दिहुली गांव में लोग भले ही इस फैसले से खुश हैं लेकिन देरी से मिले इस न्याय का उनके जीवन में अब कोई अर्थ रह नहीं गया। 24 लोगों की हत्या करने वालों को सजा चार दशक बाद हुई है।

18 नवंबर 1981 को उत्तरप्रदेश के फिरोजाबाद के दिहुली गांव में डाकुओं ने एंट्री ली और कहा - मारो इन्हें...भून डालों गोलियां से...। 24 दलितों पर तब तक गोलियां चलीं जब तक उनके शरीर से जान न निकल गई हो। औरतें और बच्चें बिलखते रहें लेकिन डकैत बिना रहम किए गोलियां बरसाते रहे। इस नरसंहार के पीछे की वजह थी गांव वालों का डकैतों के खिलाफ गवाही देना। गिरोह का सरगना था राधेश्याम और संतोष। डकैतों से जुड़े एक मुकदमे में इस गांव के दलित समुदाय के तीन व्यक्तियों ने गवाही दी थी। इस बात से डकैत नाराज थे। मामला एक पिछड़ी जाति के युवक और एक अगड़ी जाति की महिला की दोस्ती से शुरू हुआ था। डकैत राधेश्याम और संतोष अगड़ी जाति के थे। उनके साथ कई ऐसे डकैत थे जो पिछड़ी जाति के थे। उन्हीं में से एक का नाम था कुंवरपाल। डकैत राधेश्याम और संतोष के गिरोह के कुंवरपाल दलित थे। उनकी एक अगड़ी जाति की महिला के साथ मित्रता की खबर जब राधेश्याम और संतोष को हुई तो दोनों खासा नाराज थे। कुछ समय बाद कुंवरपाल की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने कुंवरपाल हत्याकांड मामले में राधेश्याम और संतोष के गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में हथियार जब्त किए। पुलिस ने इस मामले में दिहुली गांव के जाटव समुदात (दलित) के तीन लोगों को गवाह बनाया था। जब इस बात का पता डकैतों को लगा तो उन्होंने बदला लेने के लिए दिहुली में नरसंहार किया।

सहायक जिला सरकारी वकील रोहित शुक्ला के मुताबिक 18 नवंबर 1981 की शाम पांच बजे के करीब थाना जसराना क्षेत्र के दिहुली गांव में हथियारबंद बदमाशों ने घुसकर अनुसूचित जाति बस्ती में हमला बोल दिया था। घरों में मौजूद महिलाओं, पुरुष और बच्चों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी थीं। बदमाशों ने तीन घंटे तक फायरिंग की थी। इस फायरिंग में 23 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि एक घायल की इलाज के दौरान फिरोजाबाद अस्पताल में जान चली गई थी। इस नरसंहार से उस समय सरकार, शासन-प्रशासन हिल गया था। वकील शुक्ला ने बताया कि घटना की एफआईआर दिहुली के रहने वाले लायक सिंह ने 19 नवंबर को जसराना थाने में की थी। FIR में राधेश्याम उर्फ राधे, संतोष चौहान उर्फ संतोषा, रामसेवक, रविंद्र सिंह, रामपाल सिंह, वेदराम सिंह, मिट्ठू, भूपराम, मानिक चंद्र, लटूरी, रामसिंह, चुन्नीलाल, होरीलाल, सोनपाल, लायक सिंह, बनवारी, जगदीश, रेवती देवी, फूल देवी, कप्तान सिंह, कमरुद्दीन, श्यामवीर, कुंवरपाल और लक्ष्मी का नाम था। मामले की कुछ दिन जिला न्यायालय में सुनवाई चली लेकिन डकैती न्यायालय न होने के बाद केस प्रयागराज भेज दिया गया था। वहां सुनवाई के बाद मामला फिर से मैनपुरी स्पेशल जज डकैती न्यायालय भेज दिया गया था। उत्तरप्रदेश में वीपी सिंह की सरकार इस घटना के चलते सवालों के घेरे में थी। कानून व्यवस्था के सवाल दिल्ली की सड़कों तक पहुंच गए थे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री रहीं इंदिरा गांधी, मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री के साथ दिहुली गांव पहुंची थी। यहां उन्होंने लोगों को ढांढस बंधाया और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा भी किया था।

सियासी गहमागहमी

अपना नाम सामने न आने देने की जुगत

मध्यप्रदेश के बहुचर्चित परिवहन विभाग के घोटाले के मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ हो रही बैठकों के बाद हर बार प्रदेश के अधिकारी व राजनेता अपना नाम सामने न आने देने की जुगत में जुटे हुए हैं। चर्चा इस बात की है कि ईओडब्ल्यू और आईटी की टीम को जैसे-जैसे सौरभ शर्मा से दस्तावेज प्राप्त हुए वैसे-वैसे प्रदेश के उच्च स्तरीय लोगों की दिल की धड़कने तेज होने लगती है। अब देखने वाली बात यह है कि आईटी की टीम इन बड़े नामचीन व्यक्तियों के नाम के खुलासे करती है या फिर एक बार इस पूरे मामले को हनी ट्रैप की तरह दो-चार व्यक्तियों को सजा देकर रफा दफा करने जैसी गहरी चाल चलेगी।

प्रदेश सरकार को कमलनाथ ने दिखाया आईना

मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम पर बेरोजगार युवाओं से आवेदन शुल्क के नाम पर करोड़ों रूपये लूटने के आरोप लगाए हैं। कमलनाथ ने अपने इस बयान के साथ प्रदेश सरकार को आईना दिखाया कि वह कितना निचले स्तर तक भ्रष्टाचार को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। उल्लेकनीय है कि आंकड़ों के मुताबिक़ पिछले 5 वर्षों में 4 शिक्षक पात्रता परीक्षाएं आयोजित की गई, जिसमें 12 लाख से अधिक युवा शामिल हुए। इन युवाओं ने परीक्षा शुल्क के नाम पर सरकार को क़रीब 45 करोड़ रुपये की भारी भरकम रक़म चुकाई, बदले में युवाओं को बेरोजगारी ही हासिल हुई।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

98 साल पहले शुरू हुई हिस्सेदारी की लड़ाई जारी है।

20 मार्च 1927 को बाबासाहेब अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह के जरिए जातिगत भेदभाव को सीधी चुनौती दी थी। यह केवल पानी के अधिकार की नहीं, बल्कि बराबरी और सम्मान की लड़ाई थी।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

कांग्रेस का वादा है

देश में जातिगत जनगणना होगी

आरक्षण में 50% की सीमा हटेगी

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

भारतीय राजनीति में प्रतिष्ठित नाम है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

समता पाठक/जगत प्रवाह

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 में राजस्थान के झुंझुनु जिले में एक किसान परिवार में हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा किठाना गांव के स्कूल में हुई। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ से पूरी की और फिर राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्कूली शिक्षा के बाद जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के महाराज कॉलेज जयपुर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। यहां से उन्होंने फिजिक्स में BSE की डिग्री ली। साल 1978 में उन्होंने जयपुर विश्वविद्यालय में एलएलबी कोर्स में एडमिशन लिया। कानून की डिग्री लेने के लेने के बाद जगदीप धनखड़ ने वकालत शुरू कर दी और साल 1990 में उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट का ओहदा दिया गया। जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के कई हाईकोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस की। राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वकालत की। वह 1989-91 के दौरान राजस्थान में झुंझुनू (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) से 9वीं लोकसभा में जनता दल का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद सदस्य थे। वह 1993-98 के दौरान 10वीं विधान सभा राजस्थान में किशनगढ़, राजस्थान से विधानसभा के पूर्व सदस्य और राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, जयपुर के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। जगदीप धनखड़ का राजनीतिक करियर करीब 30 सालों का है। वह चंद्रशेखर की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। लोकसभा हो या विधानसभा वह जिस सदन के भी सदस्य रहे उसकी अहम समितियों में शामिल रहे हैं। 20 जुलाई 2019 को उनको पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया।

धनखड़ का राजनीतिक करियर करीब 30 वर्षों का है। साल 1989 में वह सक्रिय राजनीति में आए और इसी वर्ष 9वीं लोकसभा के लिए झुनझुनू से जनता दल के टिकट पर चुनाव जीतकर पहली बार सांसद चुने गए। 1990 में वह चंद्रशेखर की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। इसके बाद उन्होंने राजस्थान की राजनीति में भी हाथ आजमाए। 1993 से लेकर 1998 तक वह विधायक भी रहे। केंद्र सरकार ने 20 जुलाई 2019 को धनखड़ को पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। अपने बयानों और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ '36 के आंकड़ों' के लिए वह लगातार सुर्खियों में रहे हैं। उनके और ममता बनर्जी के बीच खुलकर मतभेद नजर आए थे। पश्चिम बंगाल सरकार बतौर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राज्य के निजी विश्वविद्यालयों में 'अतिथि' या 'विजिटर' के तौर पर हटाने के लिए कानून में संशोधन करने के बाद उन्हें उस पद से हटा दिया था।

युवाओं के लिए प्रेरणा है क्रांतिकारियों का जीवन

- **शहीद दिवस : क्रांति के अमर नायक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव**
- **शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले**

आज की बात

प्रवीण कक्कड़

स्वतंत्र लेखक

भगत सिंह (1907-1931)

भगत सिंह ने सिर्फ 23 साल की उम्र में ही देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनका सपना एक ऐसा भारत था, जहां सामाजिक समानता और न्याय हो। उन्होंने न केवल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया, बल्कि समाज में व्याप्त असमानता और शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाई। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने सांडर्स की हत्या की। दिल्ली असेंबली में बम फेंककर उन्होंने अंग्रेजी शासन को चुनौती दी और "इंकलाब जिंदाबाद!" का नारा लगाया। भगत सिंह ने यह साबित कर दिया कि क्रांति केवल हिंसा से नहीं, बल्कि विचारों से भी की जा सकती है।

सुखदेव थापर (1907-1931) सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। सुखदेव ने युवाओं को क्रांतिकारी विचारधारा अपनाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें समाज में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि युवा शक्ति ही देश को बदल सकती है।

शिवराम राजगुरु (1908-1931) राजगुरु एक साहसी और कुशल निशानेबाज थे। उन्होंने सांडर्स की हत्या में अहम भूमिका निभाई और भगत सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया। राजगुरु ने अपने जीवन का हर पल देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। उनका साहस और दृढ़ संकल्प युवाओं के लिए आज भी प्रेरणादायक है।

युवाओं के लिए प्रेरणा के सूत्र "इंकलाब जिंदाबाद!" यह नारा सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान है। युवाओं को अपने विचारों और कार्यों से समाज में न्याय और समानता की लड़ाई लड़नी चाहिए।

तार्किक सोच और दृष्टिकोण भगत सिंह द्वारा लिखित प्रसिद्ध निबंध "मैं नास्तिक क्यों हूं" युवाओं को अंधविश्वासों से दूर रहने और हर बात को तर्क की कसौटी पर परखने की प्रेरणा देता है। उनका मानना था कि समाज को बदलने के लिए वैज्ञानिक सोच और तार्किक दृष्टिकोण जरूरी है।

संघर्ष का महत्व भगत सिंह ने कहा था, "सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें साकार करने के लिए निरंतर संघर्ष करना भी जरूरी है।" यह संदेश युवाओं को उनके लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है।

जीव-जंतुओं के लिए खतरा है प्लास्टिक

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा

पर्यावरणविद्

प्लास्टिक कचरा जीव-जन्तुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज प्लास्टिक जीव जंतुओं के साथ साथ इंसानों के लिए भी गंभीर संकट बन गया है। प्लास्टिक का हर टुकड़ा जो कभी बनाया गया था वह आज भी हमारी दुनिया में मौजूद है। प्लास्टिक को मूल रूप से 1900 के दशक की शुरुआत में हाथी दांत और कछुए के खोल जैसी प्राकृतिक सामग्रियों की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया था।, लेकिन इसका उत्पादन चरम स्तर तक बढ़ गया है। प्लास्टिक का उत्पादन स्टील और सीमेंट को छोड़कर अन्य सभी मानव निर्मित सामग्रियों से आगे निकल गया है और अगले दशक में इसके 40 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है। एक अनुमान है कि 1950 और 2015 के बीच 7,800 मिलियन टन प्लास्टिक का निर्माण किया गया था और वह अरबों टन अभी भी दुनिया में मौजूद है। इनमें 79 प्रतिशत लैंडफिल या प्राकृतिक वातावरण में जमा होगा, 12 प्रतिशत को जलाया गया होगा और 9 प्रतिशत का पुनर्चक्रण किया गया है। प्लास्टिक कचरे से पूरी दुनिया परेशान है। प्लास्टिक की थैलियों को रीसाइकिल करना मुश्किल और महंगा है और ज्यादातर लैंडफिल साइट्स पर खत्म हो जाती है, जहां उन्हें फोटोडिग्रेड होने में लगभग 300 साल लगते हैं वे छोटे छोटे जहरीले कणों में टूट जाते हैं जो मिट्टी और जल मार्गों को दूषित करते हैं और जब जानवर गलती से उन्हें खा लेते तो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। समंदर हो या नदियाँ ,पहाड़ हो या दूर स्थित द्वीप या मैदान हो या शहर-गाँव के नाले, हर जगह प्लास्टिक के कचरे से हो रहे प्रदूषण से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। प्लास्टिक कचरा पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुँचाता है। यह जलीय जीवन को भी प्रभावित करता है, क्योंकि जलीय जीव प्लास्टिक को खा जाते हैं और इससे उनकी मौत हो जाती है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से सीसा (लैड), कैडमियम और पारा जैसा रसायन खेतों में प्लास्टिक के द्वारा प्रदूषित पानी से सिंचित सब्जियों-फल के द्वारा सीधे मानव शरीर के सम्पर्क में आते हैं जिससे कैंसर, विकलांगता, मानव एवं जीव-जंतुओं के इम्यून- सिस्टम को बचपन में ही सीधे प्रभावित कर रहे हैं। यह तथ्य विज्ञान-सम्मत हैं। फल, सब्जियां, बच्चों के दूध की बोतलें तथा खाद्य पदार्थ की पैक्ड सामग्रियाँ पूर्ण रूप से प्लास्टिक पर निर्भर हो गयी हैं। समय के साथ-साथ विसफोनेल जिससे प्लास्टिक बनता है, शरीर में रिसने लगता है और इन खाद्य-पदार्थों से मिलकर शरीर में पहुँच जाता है, इसका कुप्रभाव जानलेवा बनता है। कचरे को कम करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे, जैसे कि प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करना, प्लास्टिक कचरे को सही तरीके से निपटाना प्लास्टिक के बजाय कपड़े या पेपर की थैलियों का उपयोग करना, प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल करना आदि। एक संवेदनशील एवं जिम्मेदार सजग नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य बनता है कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिये अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। सरकार को भी नये प्लास्टिक के सामानों के उत्पादन पर नियंत्रण लगाकर प्लास्टिक के उत्पादों के उपयोग पर सख्ती के साथ प्रतिबंध लगाये। हम सभी नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि समाज के सभी वर्ग के नागरिकों को प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले प्रदूषण के खतरे से जागरूक करें। हमें प्लास्टिक के पानी की बोतलों का उपयोग बन्द करना चाहिए। प्लास्टिक के थैलियों की जगह कपड़ों की थैलियों में घर की उपयोगी साग-सब्जियां और फल एवं अन्य घर के खाने-पीने की आवश्यकता की सामग्री लेकर घर आयें। प्लास्टिक से पीछा छुड़ाने के लिये अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। पैकेजिंग उद्योगों को भी नयी सोच के साथ प्लास्टिक-प्रदूषण रोकने की दिशा में काम करना होगा और इसमें सरकार और प्रबुद्ध जनता को मिलकर सहयोग करना होगा। हमें प्लास्टिक के कचरे को अलग रखना होगा। प्लास्टिक के उपयोग पर रोकथाम ना सिर्फ हमारी आज की पीढ़ी के लिये जरूरी है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य के लिये भी आवश्यक है।

21 मार्च वन दिवस पर विशेष

वैश्विक होती दुनिया में पेड़

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

वैश्विक-फलक पर सबसे अहम गणना, जनगणना मानी जाती है। हालांकि पालतू-पशु,वन्य जीव और वृक्षों की गिनती भी होती रही हैं, लेकिन इन्हें जनगणना के मुकाबले अहमियत नहीं दी जाती। यही वजह रही कि विश्व स्तर पर वृक्षों की की गई गिनती के निष्कर्षों को समाचार माध्यमों ने उतना महत्व नहीं दिया, जितना दिया जाना चाहिए था, जबकि पेड़ों की अस्मिता पर ही मनुष्य व अन्य प्राणियों का जीवन टिका हुआ है। गोया, पेड़ एक ऐसी प्राकृतिक संपदा है, जिसका यदि विनाश होता है तो मनुष्य का सुखद जीवन भी संभव नहीं है।

जब से मानव सभ्यता के विकास का क्रम शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक वृक्षों की संख्या में 46 प्रतिशत की कमी आई है। पेड़ों की गिनती के अब तक के सबसे समग्र वैश्विक अभियान में दुनिया भर के वैज्ञानिक समूहों ने यह निष्कर्ष निकाला है। इस अध्ययन का आंकलन है कि विश्व में तीन लाख करोड़ वृक्ष हैं। यानी मोटे तौर पर प्रति व्यक्ति 422 पेड़ हैं। हालांकि यह आंकड़ा पूर्व में आंकलित अनुमानों से साढ़े सात गुना ज्यादा बताया जा रहा है। दरअसल पूर्व के वैश्विक आंकलनों ने तय किया था कि दुनिया भर में महज 400 अरब पेड़ लहरा रहे हैं। मसलन प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या 61 है। यह आंकलन व्यक्ति आधारित था, इसलिए इसकी प्रामाणिकता पर संदेह था। दरअसल दुनिया में अभी भी ऐसे दुर्गम स्थलों पर जंगलों का विस्तार है, जहां सर्वेक्षण में लगे मानव-समूहों का पहुंचना और पहुंचकर सर्वे करना आसान नहीं है। क्योंकि इन जंगलों में एक तो अभी भी रास्ते नहीं हैं, दूसरे,खतरनाक वन्य-जीवों की मौजदूगी है।

पेड़ों की यह गिनती उपग्रह द्वारा ली गई छवियों के माध्यम से की गई है। इस गणना को तकनीक की भाषा में 'सेटेलाइट इमेजरी' कहते हैं। इस तकनीक से पूरा सर्वे वन-प्रांतरों में लिया गया है। इसमें जमीनी स्तर पर कोई आंकड़े नहीं जुटाए गए हैं। इस अध्ययन की विस्तृत रिपोर्ट प्रतिष्ठित जनरल 'नेचर' में छपी है। रिपोर्ट के मुताबिक पेड़ों की उच्च सघनता रूस, स्कैंडीनेशिया और उत्तरी अमेरिका के उप आर्कटिक क्षेत्रों में पाई गई है। इन घने वनों में दुनिया के 24 फीसदी पेड़ हैं। पृथ्वी पर विद्यमान 43 प्रतिशत, यानी करीब 1.4 लाख करोड़ पेड़ उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय वनों में हैं। इन वनों का चिंताजनक पहलू यह भी है कि वनों या पेड़ों की घटती दर भी इन्हीं जंगलों में सबसे ज्यादा है। 22 फीसदी पेड़ षीतोशण क्षेत्रों में हैं।

इस अध्ययन की प्रामाणिकता इसलिए असंगदिग्ध है, क्योंकि इस सामूहिक अध्ययन को बेहद गंभीरता से किया गया है। इस हेतु 15 देशों के वैज्ञानिक समूह बने। इन समूहों ने उपग्रह चित्रों के माध्यम से वन क्षेत्र का आकलन्र प्रति वर्ग किलोमीटर में मौजूद पेड़ों की संख्या का मानचित्रीकरण में सुपर कंप्यूटर तकनीक का इस्तेमाल करके किया है। इस गिनती में दुनिया के सभी सघन वनों की संख्या 04 लाख से भी अधिक है। दुनिया के ज्यादातर राश्ट्रीय वन क्षेत्रों में हुए अध्ययनों को भी तुलना के लिए जगह दी गई। उपग्रह चित्रों के इस्तेमाल से पेड़ों के आंकलन के साथ स्थानीय जलवायु, भौगोलिक स्थिति, पेड़-पौधे, मिट्टी की दशाओं पर मानव के प्रभाव को भी आधार बनाया गया। इससे जो निष्कर्ष निकले, उनसे तय हुआ कि मानवीय हलचल और उसके जंगलों में हस्तक्षेप से पेड़ों की संख्या में गिरावट की दर से सीधा संबंध है। जिन वन-क्षेत्रों में मनुष्य की आबादी बढ़ी है, उन क्षेत्रों में पेड़ों का घनत्व तेजी से घटा है। वनों की कटाई, भूमि के उपयोग में बदलाव वन प्रबंधन और मानवीय गतिविधियों के चलते हर साल दुनिया में 15 अरब पेड़ कम हो रहे हैं। जिस तरह से भारत समेत पूरी दुनिया में अनियंत्रित औद्योगीकरण, शहरीकरण और बड़े बांध एवं चार व छह पंक्तियों के राजमार्गों की संरचनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं, उससे भी जंगल खत्म हो रहे हैं। दिल्ली में नया संसद भवन बनाने के लिए भी सैंकड़ों पेड़ काटे गए थे।

ऐसे समय जब दुनिया भर के पर्यावरणविद् और वैज्ञानिक जलवायु संकट के दिनोंदिन और गहराते जाने की चेतावनी दे रहे हैं, पर्यावरण सरंक्षण में सबसे ज्यादा मददगार वनों का सिमटना या पेड़ों का घटना वैश्विक होती दुनिया के लिए चिंता का अहम विषय है। विकास के नाम पर जंगलों के सफाए में तेजी भूमंडलीय आर्थिक उदारवाद के बाद आई है। पिछले 15 साल में ब्राजील में 17 हजार, म्यांमार में 08, इंडोनेशिया में 12, मेक्सिको में 07, कोलंबिया में 6.5, जैरे में 04 और भारत में 4 हजार प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से वनों का विनाश हो रहा है। यानी एक साल में 170 लाख हेक्टेयर की गति से वन लुप्त हो रहे हैं। यदि वनों के विनाश की यही रफ्तार रही तो जंगलों को 4 से 8 प्रतिशत क्षेत्र, सन् 2030 तक विलुप्त हो जाएंगे। 2040 तक 17 से 35 प्रतिशत सघन वन मिट जाएंगे। इस समय तक इतनी विकराल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि 20 से 75 की संख्या में दुर्लभ पेड़ों की प्रजातियां प्रति दिन नष्ट होने लग जाएंगी। नतीजतन आगामी 15 सालों में 15 प्रतिशत वृक्षों की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। इनकी विलुप्ति का असर फसलों पर भी पड़ेगा।

वृक्षों का संरक्षण इसलिए जरूरी हैं, क्योंकि वृक्ष जीव-जगत के लिए जीवन-तत्वों का सृजन करते हैं। वायु-प्रदूषण, जल-प्रदूषण, भू-क्षरण न हों, पेड़ों की अधिकता से ही संभव है। वर्षा चक्र की नियमित निरंतरता पेड़ों पर ही निर्भर है। पेड़ मनुष्य जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं, इसका वैज्ञानिक आंकलन भारतीय अनुसंधान परिषद् ने किया है। इस आंकलन के अनुसार, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पर्यावरण के लिहाज से एक हेक्टेयर क्षेत्र के वन से 1.41 लाख रुपए का लाभ होता है। इसके साथ ही 50 साल में एक वृक्ष 15.70 लाख की लागत का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ देता है। पेड़ लगभग 03 लाख रुपए मूल्य की भूमि की नमी बनाए रखता है। 2.5 लाख रूपए मूल्य की आक्सीजन, 02 लाख रुपए मूल्य के बराबर प्रोटीनों का संरक्षण करता है। वृक्ष की अन्य उपयोगिता में 5 लाख रुपए मूल्य के समतुल्य वायु व जल प्रदूशण नियंत्रण और 2.5 लाख रुपए मूल्य के बराबर की भागीदारी पक्षियों, जीव-जंतुओं व कीट-पतंगों को आश्रय-स्थल उपलब्ध कराने के रूप में करता है। वृक्षों की इन्हीं मूल्यवान उपयोगिताओं को ध्यान में रखकार हमारे ऋषि-मुनियों ने इन्हें देव तुल्य माना और इनके महत्व को पूजा से जोड़कर संरक्षण के अनूठे व दीर्घकालिक उपाय किए। इसलिए भारतीय जनजीवन का प्रकृति से गहरा आत्मीय संबंध है। लेकिन आधुनिक विकास और पैसा कमाने की होड़ ने संरक्षण के इन कीमती उपायों का लगभग ठुकरा दिया है।

पेड़ों के महत्व का तुलनात्मक आंकलन अब शीतलता पहुंचाने वाले विद्युत उपकरणों के साथ भी किया जा रहा है। एक स्वस्थ्य वृक्ष जो ठंडक देता है, वह 10 कमरों में लगे वातानुकूलितों के लगातार 20 घंटे चलने के बराबर होती है। घरों के आसपास पेड़ लगे हों तो वातानुकूलन की जरूरत 30 प्रतिशत घट जाती है। इससे 20 से 30 प्रतिशत तक बिजली की बचत होती है। एक एकड़ क्षेत्र में लगे वन छह टन कार्बन डाईआक्साइड रखते हैं, इसके उलट चार टन आक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जो 18 व्यक्तियों की वार्षिक जरूरत के बराबर होती है। हमारी ज्ञान परंपराओं में आज भी ज्ञान की यही महिमा अक्षुण्ण है, लेकिन यंत्रों के बढ़ते उपयोग से जुड़ जाने के कारण हम प्रकृति से निरंतर दूरी बनाते जा रहे हैं। तय है, वैष्विक रिपोर्ट में पेड़ों के नशट होते जाने की जो भयावहता सामने आई है, यदि वह जारी रहती है तो पेड़ तो नष्ट होंगे ही, मनुष्य भी नष्ट होने से नहीं बचेगा।

जन्मदिवस 23 मार्च पर विशेष

गरीबों का अपना आदमी: डॉ. राम मनोहर लोहिया

रघु ठाकुर
विचारक

50 के दशक से डॉ. लोहिया ने जिन बातों को कहना शुरू किया था वे समाज को बदलने वाली थी और भारतीय राजनीति के जड़ बन रहे चरित्र पर चोट करने वाली थी। आजादी और महात्मा गाँधी की मृत्यु के बाद विशेषतः जिस प्रकार कांग्रेस क्रमशः सत्ता लोलुप, अवसरवाद, परिवारवाद और राजनैतिक पतन के रास्ते पर जाने लगी थी और देश को गाँधी के रास्ते से भटकाने लगी थी ऐसे दौर में डॉ. लोहिया ने उन कमजोरियों को उजागर किया और उन्हें सुधारने के उपाय भी बताए। सात क्रांतियों के माध्यम से लोहिया ने कहा कि आज दुनिया को सात क्रांतियां जरूरी है:- आर्थिक-राजनैतिक-सामाजिक-लेगिंक-रंग आधारित, विषमताओं को मिटाना, विकेन्द्रीकरण-निशस्तीकरण और विश्व संसद। लोहिया प्रखर राष्ट्रवादी थे परन्तु अपने आप को विश्व नागरिक मानते थे। वे चाहते थे कि दुनिया की चुनी हुई संसद बने और दुनिया एक राजनैतिक इकाई बन जाए।

लोहिया ने सिद्धांत दिया कि ''कथनी और करनी'' में एकता होना चाहिए। यानि बोली अलग और आचरण अलग इस फर्क को मिटाना जरूरी है। आमतौर पर राजनेता भाषणों में बहुत उदार और मीठे होते है, परन्तु आचरण भिन्न होते है। भारतीय राजनीति की इस फैलती महामारी के प्रति लोहिया ने देश को सावधान किया और एक अर्थ में गाँधी जी के और उनके बताए सत्य के मार्ग की ओर मोड़ने का प्रयास किया।

यह वह काल था जब भारतीय राजनीति राजनैतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। दलों के नेतृत्व स्वयं भू निर्णायक और निरंकुश बन रहे थे। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा शुरू हो चुकी थी और शीर्ष व जमीन के रिश्ते टूट रहे थे। एक तरफ दलों में आंतरिक लोकतंत्र के प्रति उनकी चिंता थी और दूसरी तरफ आंतरिक लोकतंत्र का अर्थ एक प्रकार की अराजक आजादी में न बदल जाए यह भी उनकी चिंता थी। इसलिए डॉ. लोहिया ने राजनैतिक सिद्धांत गढ़ा और कहा कि ''वाणी की स्वतंत्रता होना चाहिए और कर्म पर नियंत्रण होना चाहिए''। याने दल के भीतर कार्यकर्ता को बोलने की पूर्ण आजादी हो इस आजादी को लेकर वह नेतृत्व का कोपभाजन न बने और एक बार जो निर्णय बहुमत से हो जाए तो फिर उसका पालन हो।

राजनीति और धर्म के रिश्तों को लेकर भी देश में एक प्रकार की बहस शुरू हुई थी। राजनैतिक दलों में एक धड़ा था जो मार्क्स की तर्ज पर धर्म को अफीम घोषित कर सम्पूर्णतः नकारना चाहता था और दूसरी तरफ एक जमात थी जो धर्म को पाषण पूजा-परम्पराओं और कट्टरताओं में जकड़ कर रखना चाहती थी। इस द्वन्द का मार्ग भी लोहिया ने अपने एक कथन से बताया कि, ''राजनीति अल्पकालीन धर्म है, और धर्म दीर्घकालीन राजनीति'' याने लोहिया ने समाज को बदलने के लिए कम समय और कुछ समय के सिद्धांत कमोवेश स्थाई व शाश्वत नैतिक मूल्य के बीच संतुलन साधना राजनीति का प्रमुख कर्म है, निरूपित किया था। देश के सामने उपस्थित गैर बराबरियों को मिटाना-ईसान इंसान के फर्क को मिटाना, समता और सम्पन्नता को एक साथ एक बराबरी पर रखना उनका लक्ष्य था। यह राजनीति के लिए धर्म मूल्य थे और धर्म का काम एक नैतिक और सामाजिक मूल्यों पर आधारित व्यक्ति और समाज का निर्माण करना याने दीर्घकालीन राजनीति। इसलिए लोग याने समाज में प्रचलित ईश्वरीय प्रतीकों को एक नये द्रष्टिकोण से प्रस्तुत किया। जिसमें उनके उन गुणों या मूल्यों को स्वीकार कर लिया जाए जो समाज हेतु अनुकूल है और जो गैर जरूरी घटनाएं या सूचनाएं है उन्हें छोड़ दिया जाए। इसलिए लोहिया ने कहा कि, हमें ''नीर, क्षीर, विवेक'' को कसौटी बनाना चिहए। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है ''साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय, सार-सार को गहि रहे थोथा देय उड़ाए'' लोहिया ने भारतीय जीवन में घुले मिले राम, कृष्ण, शिव को इसी कसौटी पर रखकर स्वतः नास्तिक होते हुए भी उपयोगितावादी, आस्तिकता का मार्ग बताया।

लोहिया ने महात्मा गाँधी के द्वारा बताई गई ''आखिरी पंक्ति के आखिरी आदमी'' को उठाने की कसौटी को जमीन पर उतारा। उन्होनें 50 के दशक से ही दूरस्थ और संघन वनाचलों में रहने वाले आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना सिखाया। बच्चों से लेकर बड़ों तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक के सभी वन क्षेत्रों के आदिवासी क्षेत्रों के निवासियों को अपने समतावादी आंदोलन से जोड़ा। आदिवासियों की जमीन के अधिकार-उनकी सभ्यता का संरक्षण

सिखाकर लोहिया ने लगभग देश के सभी आदिवासी अंचलों में नये आदिवासी नेतृत्व को खड़ा किया। उन्होंने हिन्द किसान पंचायत के नाम से किसानों का संगठन खड़ा कराया और कृषि क्षेत्र की बुनियादी या मानवीय समस्याओं के हल को सामने रखकर दाम बांधो नीति, फसलों का उतार-चढ़ाव-शहरों और गाँव के बीच का फर्क मिटाना आदि लक्ष्य हिन्द किसान पंचायत के माध्यम से प्रस्तुत किए। और जगह-जगह जन आंदोलन खड़े किए। उन्होंने निजी क्षेत्र की लूट और संगठित क्षेत्र के भ्रष्टाचार पर ऊंगली उठायी व दोनों की कमियों और अच्छाईओं को उजागर कर संतुलित समाजवादी व्यवस्था, सरकारीकरण के बजाय सहकारीकरण का मार्ग बताया।

लोहिया ने न केवल गरीबों, उपेक्षितों और वंचितों के साथ रिश्ता जोड़ा, उनकी पीड़ाओं को उकेरा, उनके हल सुझाएं-उन्हें बोलने की जबान दी और उनके आत्म विश्वास को जगाने के लिए ऐसे प्रतीक खड़े किए जो उन वंचित समाजों में उत्साह पैदा कर सके। लोहिया ने आज के छत्तीसगढ़ के वनांचल जो कि सिहावा नगरी के नाम से जाना जाता है, जो उनके काल में याने आज से लगभग 70 वर्ष पहले एक दुर्गम और अगम्य स्थान जैसा था वहाँ जाकर आदिवासियों को जमीन के अधिकार के प्रति जागरूक किया। इस आंदोलन में शहीद सुखराम नागे, समरीन बाई, विसाईन बाई, मगलूराम जैसे सेकड़ों संघर्षशील आदिवासियों नेताओं को तैयार किया और उस काल के दौरान जो आदिवासी शहरी बाबू को देखकर डरकर छुप जाता था उसे बोलना, लड़ना सिखाया उसमें आत्मविश्वास जगाया और उसे वैश्विक बराबरी से जोड़ा। लोहिया ने राय बरेली में स्व. फिरोज गाँधी के खिलाफ स्व. नंद किशोर नाई को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से महारानी विजया राजे सिंधिया के खिलाफ सुक्खोरानी नामक जमादारीन को खड़ा किया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ खुद खड़े हुए और एक गरीब व्यक्ति भी प्रधानमंत्री और राजा-महाराजा के खिलाफ खड़ा हो सकता है, यह आत्मविश्वास पैदा किया।

देश के गरीबों के साथ किसान, मजदूरों के साथ उनका नाता इतना गहरा बन चुका था यह उस समय नजर आया जब लोहिया बीमार होकर दिल्ली के सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। रीवा की एक पान बेचने वाली महिला लोहिया के बीमारी के दिन से अपनी दुकान बंद कर दिल्ली पहुंची थी और तत्कालीन विलिंगडन अस्पताल के सामने फुटपाथ पर दिन-रात बैठकर लोहिया के स्वस्थ होने का इंतजार करती थी। लोहिया की मृत्यु तक वह दिल्ली में ही रही घर वापिस नहीं आई। ऐसे कितने ही गरीबों को लोहिया के अस्पताल से वापिस आने का इंतजार था कि लोहिया स्वस्थ होकर वापिस आयेंगे और फिर संसद और संसद के बाहर गरीबों की आवाज उठायेंगे। यह दुर्भाग्य ही था कि उन सभी की आशा पूरी नहीं हुई। लोहिया जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे थे। अर्ध बेहोशी की हालात में भी जब वे बोलते थे तो पूछते थे कि उ.प्र. के किसान आन्दोलन का क्या हुआ? किसानों की माँगों का क्या हुआ? ऐसा किसानों का हमदर्द कौन हो सकता है? वह हर विषमता के खिलाफ थे, इसलिये उन्होंने अपना इलाज एक सरकारी अस्पताल में कराया, जहाँ की चिकित्सा बहुत ही सामान्य स्तर की थी।

लोहिया यह जानते थे कि वह जिन बातों को उठा रहे है, वे तत्कालीन समाज से बहुत आगे की है। परन्तु वह यह भी जानते थे कि आज या कल देर सवेरे समाज को इन बातों को स्वीकार करना होगा। आज से 70 वर्ष पहले नर-नारी की समानता की बात को उठाना, भारत के लिये मजबूत बनाने को सावित्री नहीं द्रौपदी चाहिये जिसमें बोलने की क्षमता हो, मुकाबला करने की क्षमता हो, साहस हो, यह लोहिया कह रहे थे। अपने विचारों के प्रति उनका विश्वास इतना गहरा था कि अन्ततः समाज को इन्हें स्वीकार करना ही होगा। इसलिये उन्होंने कहा कि ''लोग मेरी बात सुनेंगे, शायद मेरे मरने के बाद पर सुनेंगे जरूर''। उनके पास धन, मकान, सम्पत्ति नहीं थी, न इनकी उन्हें दरकार थी। उनकी सबसे बड़ी पूँजी तो गरीबों का, दुखियों का उनके प्रति विश्वास था। इसलिये उन्होंने कहा था कि ''मेरे पास कोई पूँजी नहीं है सिवाय इसके कि गरीब मुझे अपना आदमी मानते है''।

लोहिया की बात फिर सही होती दिख रही है, न केवल देश ने बल्कि दुनिया ने लोहिया को पढ़ना, खोजना और समझना शुरू किया है। कांग्रेस भी अब इस बात को महसूस करने लगी है कि लोहिया का विरोध व्यक्ति का विरोध नहीं किसी संस्था का विरोध नहीं बल्कि उन उभरती हुये राजनैतिक विकृतियों का विरोध था जो सम्पूर्ण राजनीति को बिगाड़ती है, और बदलाव के हथियार को भौथरा करती है। यह भी अच्छा संकेत है कि, अब देश व कांग्रेस के लोगों ने लोहिया के आजादी के आन्दोलन को स्वीकारना शुरू किया है। म.प्र. के मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी 2020 के संदेश में आजादी के आन्दोलन के नायकों में लोहिया का उल्लेख किया है, इसके लिये वे साधुवाद के पात्र है। इतिहास को न मिटाया जा सकता, न दबाया जा सकता बल्कि भविष्य को सुधारने का उपाय बनाया जा सकता है।

नहीं होने देंगे किसी के साथ अन्याय, सबकी खुशहाली सरकार का संकल्प : मुख्यमंत्री योगी

-अमित राय

जगत प्रवाह, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि गरीबों की जमीन पर यदि किसी ने कब्जा किया है तो तत्काल जमीन को कब्जा मुक्त कराने के साथ दबंगों को सबक सिखाया जाए। किसी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ कानून सम्मत कड़ा एक्शन लिया जाए। सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देने और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है। गोरखपुर में होलिकोत्सव मनाने के बाद सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के बाहर कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक वह खुद पहुंचे और एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ सीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जनता दर्शन में एक व्यक्ति ने दबंगों द्वारा जमीन कब्जा किए जाने की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद प्रशासन व पुलिस के अफसरों को निर्देशित किया कि जमीन कब्जा की शिकायत पर त्वरित एक्शन लिया जाए। जमीन कब्जामुक्त होनी चाहिए, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी दबंग किसी की जमीन पर कब्जा न करने पाए।

मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करा कर शासन में उपलब्ध कराया जाए। राजस्व व पुलिस से जुड़े मामलों को उन्होंने पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उसकी मदद की जाए।

खाखरा वाले मंदिर का टिमरनी जनपद उपाध्यक्ष अनिल वर्मा द्वारा किया जा रहा है निर्माण

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह, टिमरनी। रहटगाव क्षेत्र के प्रसिद्ध खाखरा वाले बाबा का मंदिर का टिमरनी जनपद उपाध्यक्ष अनिल वर्मा द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसकी तराई स्वयं के द्वारा की जा रही है यह स्थान वनगांव और आलमपुर के बीच मुख्य सड़क पर स्थित है। अनिल वर्मा ने बताया कि यहां पर अपने स्वयं के पैसों से तीन मंदिरों का निर्माण करा रहे हैं जिसमें नरसिंह बाबा मां दुर्गा शंकर जी का मंदिर बना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह स्थान क्षेत्र का प्रमुख आस्था का केंद्र है यहां से रोजाना आवागमन करने वाले अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अगरबत्ती नारियल चढ़ाकर पूजा करते हैं। यहां वर्मा परिवार द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। गौरतलब है कि वर्मा द्वारा रहटगाव अजनाल नदी के किनारे पर तकरीबन 03 लाख की लागत से स्वागत द्वार भी बनाया जा रहा है जो रहटगाव क्षेत्र की खूबसूरती में चार-चांद लगाएंगे एवं उनके द्वारा पूर्व में क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर स्वयं के व्यय से हेडपंप भी लगाए गए हैं।

जिले के 229 माध्यमिक शिक्षकों को फरवरी माह का नहीं मिला वेतन

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह, नर्मदापुरम। जिले के करीब 229 माध्यमिक शिक्षकों को फरवरी माह का वेतन नहीं मिलने का मामला सामने आया है। इस गंभीर विषय को लेकर शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश के संभागीय अध्यक्ष राजेश पांडे द्वारा अनेक कर्मचारी के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन आयुक्त नर्मदापुरम, कलेक्टर, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी सहित जिला कोषाधिकारी के नाम सौंपा गया है। जिसमें अवगत कराया गया है कि माखन नगर ब्लॉक की शालाओं में सेवारत 229 माध्यमिक शिक्षकों को माह फरवरी 2025 का वेतन आज दिनांक तक भुगतान नहीं किया गया है। इसके विपरीत सभी ब्लॉकों में होली त्यौहार के पूर्व भुगतान किया जा चुका है। विकासखंड कार्यालय (शिक्षा) माखननगर एवं जिला कोषालय अधिकारी से दूरभाष पर संपर्क किया गया तो उनके द्वारा भुगतान वित्त विभाग के आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या उत्पन्न होना बताया जा रहा है। शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश के संभागीय अध्यक्ष राजेश पांडे ने वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह करते हुए बताया कि कर्मचारियों को त्योहार के पूर्व वेतन न मिलने के कारण आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश कर्मचारियों के द्वारा कर्ज लेकर हाउस लोन की किस्त अदा की गई, त्यौहार हर्षोल्लास से नहीं बना पाए और भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। माह फरवरी 2025 का वेतन शीघ्र भुगतान करने का आग्रह किया गया है। जिससे माध्यमिक शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो सके और वह अपना शिक्षण कार्य शांति पूर्ण संपादन कर सकें।

फीका रहा होली का त्यौहार, कमिश्नर-कलेक्टर तक पहुंचा मामला!

कलेक्टर ने तमाम बुनियादी सुविधाओं की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित कराने के दिये निर्देश

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह, विदिशा। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने नटेरन विकासखण्ड क्षेत्र के उपार्जन केन्द्रो का भ्रमण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपार्जन केन्द्रो पर शासन के दिशा निर्देशानुसार तमाम बुनियादी सुविधाओं की शत प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश उपार्जन एजेन्सियों को दिए हैं। कलेक्टर सिंह ने भ्रमण के दौरान उपार्जन केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर गेंहू विक्रय करने हेतु आए किसानों से संवाद कर उपार्जन सुविधाओं का जायजा लिया। गौरतलब हो कि जिले में 185 केन्द्रों पर उपार्जन कार्य संचालित किया जा रहा है। इन केन्द्रों पर पंजीकृत किसानों के द्वारा स्लॉट बुक कर विक्रय हेतु गेंहू लाया जा रहा है। प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर 2600 रूपए प्रति बोरा के मान से गेंहू खरीदी कार्य किया जा रहा है जिसमें 175 रूपए बोनस राशि भी सम्मिलित है।

कलेक्टर सिंह ने विदिशा तहसील के भूमिजा वेयर हाउस (हिनोतिया समिति), उदय वेयर हाउस, सूर्य वेयर हाउस (कागपुर समिति), नटेरन तहसील के सावरियां वेयर हाउस (विपणन सोसायटी), लज्जा वेयरहाउस (आमखेड़ा सूखा समिति) पर स्थापित उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर केंद्र पर आवश्यक सुविधाओं, टैग, धागा, तौल कांटा किसानों की बैठने की उत्तम व्यवस्था का जायजा लिया। उदय वेयर हाउस पर पर्याप्त सफाई न होने पर सफाई करने के सख्त निर्देश दिए और ऑपरेटर सोसाइटी मैनेजर और सर्वेयर को औसत गुणवत्ता का गेहूं खरीदी करने के निर्देश दिए। लज्जा वेयरहाउस में उपस्थित किसानों से चर्चा करके खरीदी का फीडबैक लिया गया जिसमें किसान द्वारा बताया गया कि उपार्जन केंद्र पर गेहूं विक्रय करना उनको सरल और भरोसेमंद है और परिवहन का खर्चा भी कम लगता है उपार्जन केंद्र पर किसानों को सभी सुविधाएं मिल रही है। कलेक्टर सिंह ने खरीदी केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान समितियों को निर्देशित किया।

उपार्जन केन्द्रों का जायजा लिया

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)